

कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं.	70

दिनांक 19 नवम्बर , 2019 को आयोजित 69 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को 69 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं।
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं.	70

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	वर्तमान स्थिति
1	15.06.2018	Dedicated Certificate Officer की नियुक्ति का मामला	Dedicated Certificate Officer एवं अन्य कर्मचारियों के कार्यालयीय खर्च की प्रतिपूर्ति बैंको द्वारा किये जाने के राज्य सरकार के सुझाव के अलोक में बैंको द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को पत्रांक SLBC/18-19/53 दिनांक 15.06.2018 के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, जिसमे बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि से 5% की राशि सरकारी कोष में जमा करने की सहमति दी गयी थी। 23.05.2019 ,को मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे हुए बैठक मे संविदा पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी निर्देश दिये गए है। उक्त निर्देश के आलोक मे सभी जिलों मे लंबित नीलाम पत्रों की संख्या के अनुसार नीलाम पत्र पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों (संदेशवाहक,पेशकार-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर) की संविदा पर नियुक्ति एवं उनपर होने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन कर, संबंधित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध मे विभाग के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। अद्यतन जानकारी संबंधित विभाग से अप्राप्त है।
2	23.07.2018	बैंको को सरकारी भूमि का आवंटन का मामला	इस संदर्भ मे उपायुक्त रांची के द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पर संबंधित बैंको की आपस मे बैठक हुई जिसकी परिचर्चा के आधार पर पत्र सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को मूल्य में संशोधन तथा अन्य तीन मुद्दे पर पत्र प्रेषित किया गया है। संबंधित विभाग से अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
3	23.07.2018	land records को अद्यतन किया जाना	राज्य में land records को अद्यतन (dizitization) किये जाने के बावजूद इसके regular updation नहीं किये जाने के कारण वास्तविक जमीन मालिक के सही पहचान में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है। राज्य सरकार से अनुरोध है की Current Holders का नाम जल्द से जल्द पोर्टल मे अपडेट किया जाए ताकि बैंको के ऋण प्रवाह मे तीव्रता लायी जा सके। कई राज्यों मे ऑनलाइन LPC तथा ऑनलाइन Chargecreation की सुविधा उपलब्ध है, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि बाकी राज्यों की भांति यह सुविधा झारखंड मे भी उपलब्ध करायी जाए। संबंधित विभाग से अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
4	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों मे नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराये जाने के मुद्दे को RBI के सुझाव के आलोक में पुनः शामिल किया जा रहा है और इस विषय पर सरकार से वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी अपेक्षित है।

5	15.05.2019	किसान क्रेडिट कार्ड से छूटे हुए योग्य किसानों का ब्योरा बैंको को उपलब्ध करवाना	SLBC द्वारा राज्य सरकार के कृषि विभाग से निवेदन किया गया है कि जिन योग्य किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, उसका ब्योरा बैंकों को मुहैया कराए जाँ ताकि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड तय सीमा में दिया जा सके। 68वीं बैठक में राज्य सरकार के कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर वंचित किसानों की सूची बैंक / SLBC को उपलब्ध करायी जाए ताकि KCC तथा रुपये कार्ड के संवितरण में राज्य में गति प्रदान की जाए। विभाग द्वारा संबन्धित सूची विभाग के द्वारा SLBC को CD के माध्यम से दिया जा चुका है।
---	------------	--	---

बैंक से संबंधित मामले/ATR

बैंकों से संबंधित मामलों को 61वीं SLBC की बैठक से SLBC द्वारा ATR के रूप में discuss किये जाने का प्रावधान किया गया है। पिछली SLBC की 69 वीं बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, उन मुद्दों को सभी संबंधित बैंको एवं LDMs को उनके द्वारा उचित कार्यवाही करने के लिए ATR के format में भेजा गया था, जिससे संबंधित compiled रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के पूर्व उन बैंको एवं LDMs का उल्लेख जरूरी है जिन्होंने बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद SLBC को ATR प्रेषित नहीं किया है। ये बैंक हैं- Karur Vasya Bank, Indus Ind Bank और Kotak Mahindra Bank .

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ सं-6 से 13 पर संलग्न है।

Overall Performance एवं Incremental performance के आधार पर बैंकों का चयन:

क) Overall Performance के आधार पर बैंकों के द्वारा प्राप्तांक के अनुसार चयन किया गया निम्नलिखित बैंक :

क्रम सं	बैंक के नाम	प्राप्तांक	इससे संबंधित मानकों पर विस्तृत प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 20 से 23 में दर्शाया गया है।
.1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	192	
.2	बैंक ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद बैंक	162	

ख) Incremental Performance के आधार पर बैंकों के द्वारा प्राप्तांक के अनुसार चयन किया गया निम्नलिखित बैंक :

क्रम सं	बैंक के नाम	प्राप्तांक	इससे संबंधित मानकों पर विस्तृत प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 24 से 28 में दर्शाया गया है।
.1	बैंक ऑफ बरोदा	84	
.2	एचडीएफसी बैंक	83	

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	13.02.2020
बैठक सं.	70

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2019	Bench Mark
1	Deposit	210626.45	218100.64	217590.01	
	CASA Deposit	97523.12	99896.90	100340.79	
2	Credit	94002.59	95562.14	92883.04	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	32466.00	29465.43	27980.07	
4	Total Credit	126468.59	125027.57	120863.11	
5	CD Ratio	60.04	57.33	55.55	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	50898.32	52924.75	57816.34	
7	Share of PSA to Total Advances (%)	54.15%	55.38%	62.25%	40
8	Agricultural Advances	14367.67	14864.80	15606.45	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	15.28%	15.56%	16.80%	18
10	i. Micro & Small Enterprises Advance	21958.79	24189.37	27840.73	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	23.35%	25.31%	26.97%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	56.94%	56.60%	52.14%	
11	Advances to Weaker Sections	15625.68	16334.11	19764.81	
12	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	16.62%	17.09%	21.27%	10
13	DRI Advances	34.26%	32.59	36.39	
14	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.04%	0.04%	0.04%	1
15	Advances to Women	10503.06	13027.82	12736.19	
16	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	11.17%	13.63%	12.85%	5
17	Advances to Minorities (Amount)	5733.03	6113.46	6705.18	
18	Share of Advances to Minorities under PSA (%)	11.27%	11.55%	11.59%	15
19	Gross N.P.A	5657.68	5711.86	5408.05	
	Provision	2813.78	2820.73	2740.85	
	Net NPA	2843.90	2891.13	2719.68	
	Gross NPA Percentage	6.01%	5.98%	5.82%	
	Net NPA Percentage	3.02%	3.02%	2.92%	
20	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1472	1487		
	Semi-Urban	752	757		
	Urban	783	855		
	Total	3007	3099		
	BranchNetwork-Smal Finance Bank		22		
	Payment Banks		64		
	Total Branch including SFB		3185		
21	ATM installed in Jharkhand	3347	3192		
	ATM-Smal Finance Bank		31		
	Total ATM		3223		

*Annexure- 4(a)&5, As per Annex - 1, Annex-2, Annex-3, Annex-4, Annex -5

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 31 दिसम्बर, 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक रूपये 6964 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है। वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 3.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

31 दिसम्बर 2019 को राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट पिछले वर्ष की तुलना में रूपये 1119.50 करोड़ की गिरावट दर्ज की गयी हुई। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.19% की गिरावट है। विभिन्न बैंको से प्राप्त इस तिमाही के आंकड़ों के अनुसार निम्न प्रमुख बैंको के ऋण प्रवाह में पिछले वर्ष (दिसम्बर 2018) की तुलना में मुख्यतः गिरावट दर्ज की गयी है:

(क) SBI-1982.31 करोड़ (ख) इलाहाबाद बैंक-660.74 करोड़ (ग) केनरा बैंक-1687.59 करोड़ (घ) ICICI बैंक-495.94 करोड़

क्रेडिट – जमा अनुपात (C.D Ratio)

31.12.2018 (60.04 %) की तुलना में 31.12.2019 (55.55%) में CD ratio में गिरावट दर्ज की गई है, परन्तु पिछली कई तिमाही में बैंकों का सीडी अनुपात में गिरावट हो रही है। CD ratio सितम्बर 2019 में 57.33% था, जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 60% से काफी कम है। मार्च '19 के तुलना में कुल क्रेडिट में 2679.10 करोड़ एवं RIDF में 12959.06 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है जबकि कुल जमा में 6963.56 करोड़ की वृद्धि हुई है। दिसम्बर '18 एवं दिसम्बर '19 के तुलना करने पर कुल जमा में 6963.56 करोड़ की वृद्धि के समक्ष कुल ऋण में 1119.50 करोड़ की गिरावट हुई है तथा **Credit as per place of utilization & RIDF** में भी 4485.93 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है। सभी बैंकों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। निम्न प्रमुख बैंको के क्रेडिट – जमा अनुपात में दिसम्बर 2018 की तुलना में मुख्यतः गिरावट दर्ज की गयी है:

(क) SBI-3.87 (ख) इलाहाबाद बैंक-7.38 (ग) केनरा बैंक-5.36 (घ) HDFC बैंक-13.73 (च) ICICI बैंक-50.29 (छ) लक्ष्मी विलास बैंक-71.32

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.59 % की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 62.25% है। जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 दिसम्बर 2018 की तुलना में कृषि ऋण में इस तिमाही तक 1238.67 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी है। साथ ही साथ 31 मार्च 2019 की तुलना में भी इस तिमाही में कृषि अग्रिम में वृद्धि दर्ज की गयी है। मार्च, 19 को कृषि ऋण 14864.80 करोड़ था जो कुल अग्रिम का 15.56 % था। इस तिमाही में यह बढ़ कर 15606.45 करोड़ हो गया है जो कुल अग्रिम का 16.80% है। कृषि ऋण के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में ₹. 2583.58 करोड़ संवितरित किये गए हैं, हालाँकि यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% से कम होने के कारण एक चिंतनीय प्रश्न है। बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक एवं कृषि उपसमिति में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतु अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंको एवं अन्य हितधारकों को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा।

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

31 दिसम्बर 2019 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 19764.81 करोड़ (21.27 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है। वर्ष दर वृद्धि 26.48 % दर्ज की गई है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

31 दिसम्बर 2019 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) ₹. 12736.19 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 12.85 % है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है। वर्ष दर वृद्धि 21.26 % दर्ज की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

31 दिसम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 6705.18 करोड़ है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 11.59% है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है। वर्ष दर वृद्धि 16.95 % दर्ज की गई है। इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

31 दिसम्बर 2019 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के **MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15**, दिनांक **01.07.14** के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण-जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS		31st Dec, 2018	31st Dec, 2019
Aggregate Deposits		210626.12	217590.01
CORE ADVANCES	97523.12		92883.04
As per place of Utilization	26162.08		21792.19
RIDF	6303.91		6187.87
NET ADVANCES	126468.59		120863.11
ऋण-जमा अनुपात		60.04	55.55

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि मार्च 2019 की तुलना में राज्य का CD Ratio 57.33% से कम होकर दिसम्बर 2019 में 55.55% रह गया है। बैंको के समग्र ऋण में गिरावट दर्ज हुई है और हमारा core CD Ratio 43.82% से घटकर 42.69% हो गया है। SBI एवं CANARA Bank के कुल ऋण में पिछली तिमाही के मुकाबले में 562 करोड़ एवं 3223 करोड़ क्रमश की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि अगर Canara Bank के द्वारा इस तिमाही में reporting किए हुए आंकड़ों को हटा दिया जाए तो CD ratio में वृद्धि दर्ज हुई है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक संख्या	70

**4.1 वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के तहत
उपलब्धियों की समीक्षा : 31 दिसम्बर 2019 तक**

31 दिसम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2018-19)	ACHIEVEMENT IN AFY 2018-19		ANNUAL TARGET (2019-20)	ACHIEVEMENT IN AFY 2019-20	
	AMT.	AMT	%	AMT.	AMT	%
1	5	6	5	5	6	7
Agriculture	8336.60	3824.82	45.88%	9026.04	3214.31	35.61%
MSME	8560.35	9285.95	108.47%	10270.11	8247.87	80.30%
OPS	4213.60	2171.67	51.54%	2817.51	2665.95	94.62%
Total Priority	21110.55	15282.44	72.39%	22112.66	14128.13	63.89%
Non Priority	8773.34	11744.84	133.87%	11921.92	7362.13	61.75%
Total	29883.89	27027.28	90.44%	34034.58	21490.26	63.14%

कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न जिलों एवं बैंको द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को पृष्ठ सं-33 में दर्शाया गया है।

टिप्पणियां :

- ✚ वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय तिमाही के दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 63.14 % समग्र ऋण का संवितरण हुआ है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के तृतीय तिमाही में हुई 69.72 % संवितरण की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, परंतु सभी बैंको के सामूहिक प्रयास से आगामी महीनों में इसमें अपेक्षित वृद्धि लायी जा सकती है।
- ✚ कृषि क्षेत्र में कुल वार्षिक योजना के विरुद्ध केवल 35.61 % ऋण का संवितरण ही हो पाया है। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।
- ✚ MSME sector में इस वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा MSME के वार्षिक बजट के विरुद्ध 80.30 % की उपलब्धि सराहनीय है।
- ✚ 2019-20 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-6 में दर्शाया गया है एवं Agriculture Loan में बैंकवार एवं जिलावार segment wise संवितरण और o/s का रिपोर्ट annexure-7(i) से 7(iv) में दिया गया है।

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक संख्या	70

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार रू. 15600.46 करोड़ है जो सकल ऋण का 16.80% है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुनः बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	Disbursement during 2019-20		Outstanding In KCC A/Cs As of 31.12.2019	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	299904	1110.40	1369827	5235.93
Pvt. Banks	49474	198.38	62597	294.28
Total	349378	1308.78	1432424	5530.21
RRB	54177	374.35	376942	1621.33
Co-op Banks	907	3.70	11023	36.36
Total	55084	378.05	387965	1657.69

(KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है)

सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। दिनांक 31.12.2019 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार कुल 1818397 eligible KCC खातों में से 1485807 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1671108 खातों में (91.90%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं। (विवरण पृष्ठ सं-35 एवं 36 में संलग्न है।

- ❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 37 एवं 38 पर दर्शाया गया है।
- ❖ Small & Marginal Farmers तथा Medium & Large किसानों को वितरित ऋण से संबंधित प्रतिवेदन पृष्ठ सं . 39 एवं 40 में संलग्न किया गया है।
- ❖ राज्य सरकार के द्वारा झारखंड में कुल कृषकों की संख्या 39.00 लाख बतायी है तथा केसीसी से वंचित कृषकों की संख्या 3.17 लाख है। प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 91.89 % किसानों को विभिन्न बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया है। शेष 8.11 % बचे हुए किसानों को KCC से आच्छादित करने की आवश्यकता है। सभी LDMs तथा बैंकों को एकीकृत रूप से इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। जिलावार विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 34 (a) में संलग्न है।

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

(Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular	Outstanding position as at the end of			
		Dec 2018	Dec 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)		
MICRO & SMALL ENTERPRISES					
1	Micro Enterprises	Accounts	676	642	
		Amount	12504.36	14554.46	
2	Small Enterprises	Accounts	51	49	
		Amount	9454.43	10565.71	
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)	Accounts	727	691	
		Amount	21958.79	25120.17	
MEDIUM ENTERPRISES					
4.	Total of Medium Enterprises	Accounts	08	7.03	
		Amount	2434.89	2367.82	
MSME					
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)		Accounts	735	708	
		Amount	24393.68	27899.45	
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	56.94%	57.93%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	23.35%	25.35%

(MSME रिपोर्ट –annexure-9)

COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE)

(Position as on 31.12.2019)

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		TOTAL	
A/C	Amt	A/C	Amt.
574	20939.06	140	9286.97

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 42 में सलग्न है)

टिप्पणियां

- ✚ झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध दिसम्बर , 2019 मे 57.93 % है। हालाँकि पिछले वर्ष माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी 56.94 % थी।
- ✚ पिछले वर्ष की तुलना मे MSME सैक्टर मे 3505.77 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है।
- ✚ बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य मे, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 5.74 लाख (लगभग) MSE ऋण खातें हैं, जो CGTMSE coverage के लिए eligible हैं, परंतु इनमे से केवल 1.40 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 24.39 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है | PSB Loans in 59 Minutes से सम्बंधित रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-44 एवं 45 में दिया गया है |

5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी। परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है।

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.19 से 31.12.19 तक)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
Sanctioned	438540	1197.42	46944	727.14	10267	600.03	495751	2524.60
Disbursed	438439	1192.65	46867	685.68	10246	563.20	495552	12441.54

(राशि करोड़ में)

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में Micro Finance Institutions के द्वारा लगभग 332257 खातों में रु 1377.44 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और 331960 खातों में रु 1298.30 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में सभी बैंको एवं Micro Finance Institutions के द्वारा सम्मिलित रूप से इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है :

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	No.	AMT	No.	AMT.	No.	AMT.	No.	AMT.
Sanctioned	750945	2114.13	64559	991.36	12504	796.54	828008	3902.05
Disbursed	750844	2108.46	64203	904.78	12465	726.60	827512	3939.85

(राशि करोड़ में)

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-46 एवं 47 में सलग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 31.12.2019 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	Male Beneficiaries	Out of total Beneficiaries, SC/ST Beneficiaries	Loan Sanctioned Amt (Rs in Cr)
252	217	35	39	52.80

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-48 में सलग्न है।)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 31.12.18	As on 31.12.19				Total As on 31.12.19	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSEMENT DURING FY 2019-20
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	69256	62401	1506	684	336	64927	-88.83 Crore	5584
Amount (In crore)	3266.59	3090.28	60.75	22.35	4.38	3177.76		311.16

(Annexure-10)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के त्रितीय तिमाही तक शिक्षा ऋण के तहत कुल 5584 खातों में 311.16 करोड़ रु की राशि के संवितरण की रिपोर्टिंग की गई है।
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति (annexure -10 A) इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में)	संख्या	राशि (रु करोड़ में)
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2019-20)			5584	311.16
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण			5196	264.63
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	739	39.96	720	15.04

5.4 आवास ऋण

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन (रु .करोड़ में)

Particulars	Up to 31.12.18	31.12.2019				Total Up to 31.12.19	Growth in H/Loan Y-on-Y	Disbursement in AFY 2019-20
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Bank s			
खाता की सं.	80136	70898	10493	1487	126	83004	+1390. 35Crore	7882
राशि	8812.19	8719.52	1371.56	101.51	9.95	10202.54		1340.79

(रिपोर्ट -annexure-11)

आवास ऋण के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 15.78 % की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष-दर-वर्ष 1390.35 करोड़ की वृद्धि हुई है।

**5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF
BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)**

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2019 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु. करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2018		% Share	31 दिसम्बर, 2019		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
50898.32	5733.03	11.26%	57816.34	6705.18	11.59%

(रिपोर्ट -annexure-13)

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2019 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु. करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2018		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 दिसम्बर, 2019		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
94002.59	10503.06	11.17%	92883.04	12736.19	13.71 %

(रिपोर्ट -annexure-13)

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

31 दिसम्बर, 2019 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2018		DRI Percentage in Gross Credit	31 दिसम्बर, 2019		DRI Percentage in Net Credit
Gross Credit	DRI		Gross Credit	DRI	
94002.59	34.26	0.04%	92883.04	36.39	0.04%

(रिपोर्ट -annexure-12)

5.5.4 SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रु. करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2018		% achievement	31 दिसम्बर, 2019		% Achievement
Gross Credit	Loans to SC/ST		Gross Credit	Loans to SC/ST	
94002.59	11457.37	12.19%	92883.04	12181.50	13.11%

(रिपोर्ट -annexure-13)

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 313895 SHGs के S/B खाते हैं, जिनमें से 201419 खातों का credit linkage है, जिसमें कुल रु 2355.40 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रु 1108.43 करोड़ है।

(रिपोर्ट- Annexure-15)

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2019 तक) Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March 2019	उपलब्धि Achievement in AFY- 19-20	Cumulative achievement till date since Inception
No of Blocks	263	-	263
No of Villages	21340	4559	25899
Total No of SHGs supported By SRLM	193165	44805	237970
Total family supported by SRLM	2331272	531437	2862709
No of SHG receiving R.F	83006	11522	94528
Amt. of RF disbursed (Rs. in Lakhs)	12413.71	1727.315	14141.025
No of SHG receiving CIF	37074	208	37282
Amt. of CIF disbursed (Rs. in Lakhs)	20527	104	20631
No of SHG credit linked with Banks	62910	55316	105498
Amt. of Credit availed from Banks (Rs. in Lacs)	-	52406	142689.43

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय तिमाही तक बैंको द्वारा आजीविका के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 51075 SHGs को credit लिंक किया गया है। (JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार लक्ष्य एवं प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या- 52 से 53 तक दिया गया है।)

JSLPS द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 55316 SHGs को credit लिंक किया गया है। जो कि कुल लक्ष्य का 74% है। उम्मीद है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी एसएचजी Credit linkage का लक्ष्य बैंको द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या- 54 से 55 तक दिया गया है।

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	13.02.2020
बैठक की संख्या	70

**वित्तीय समावेशन एवं
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3724	454	Nil	5288	5535

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -58 एवं 59 }

B Online transaction करने वाले BC की स्थिति

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
8473	8733	5527	2639	567

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -60}

❖ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बैंको द्वारा कुल नियुक्त BC की संख्या में 2376 की वृद्धि हुई है। हालांकि 100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या में गिरावट दर्ज की गयी है।

C. PMJDY के तहत 31.12.2019 तक खोले गए खातों की स्थिति वाई

31.12.2019 तक खोले गए खातों की संख्या			PMJDY खातों में जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
9584486	3558095	13142581	10428170	11365469	8978821	8782689	8291587

{ रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -61 एवं 62 } NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

❖ पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या तथा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या में इजाफ़ा हुआ है। पिछले वर्ष कुल संवितरित किए गए Rupay Card में से activated rupay कार्ड का प्रतिशत 71.13% था जो इस वर्ष बढ़ कर 79.51 % हो गया है। यद्यपि पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 10428170 रूपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रूपे कार्ड में से केवल 88782689 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमें से भी अब तक केवल 8291587 खातों में रूपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रूपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरूरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबंधित बैंकों से प्राप्त आंकड़ा पृष्ठ संख्या-63 में दर्शाया गया है |

**प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु,
लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :**

दिनांक: 31.12.2019 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-

PMJJBY	PMSBY	APY	
Total Enrolment	Total Enrolment	Enrolment during 2019-20	Total Enrolment since inception
974203	3834114	163115	506875

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-64 संलग्न है)

- ❖ इस वर्ष APY enrollment पिछले वर्ष की तुलना में 58% ज्यादा हुआ है। APY PER BRANCH ENROLLMENT से संबंधित रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 57 (a) में संलग्न है। इस वित्तीय वर्ष में APY per branch enrollment 44.43 से बढ़कर 51.82 हो गया है। APY enrolment since inception भी दिसम्बर 2018 तिमाही के मुकाबले 288339 से बढ़कर 506875 हो चुका है।

वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गाँवों में बैंकिंग शाखा खोलने संबंधित रोडमैप

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था। झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिह्नित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमें से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है, बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था।

आरबीआई के नये दिशा निर्देश के अनुसार सप्ताह में **कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे** एक नियत स्थल पर कार्य कर रहे BC को **बैंकिंग आउटलेट**, माना जा सकता है। इस निर्देश के अनुसार निर्धारित सभी 137 गाँव में बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके हैं।

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं	70

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबंधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2019	Variation over last FY
Advances	94002.59	95562.14	92883.04	(-)1119.55
Gross NPA	5657.68	5711.86	5408.05	(-)249.63
Provision	2813.78	2820.73	2740.85	(-)72.93
Net N.P.A	2843.90	2891.13	2719.68	(-)124.22
Percentage of Gross NPA	6.01%	5.98%	5.82%	(-)0.19%
percentage of Net NPA	3.02%	3.02%	2.92%	(-)0.10%

(रिपोर्ट- annexure-18(A)and 18(B))

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A), एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है | रु 5426.05 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 5.82 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है | हालांकि मार्च 2019 के एनपीए स्तर से गिरावट दर्ज की गई है।

(विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलग्रक के रूप में दर्शाये गए हैं |)

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qtr.		Cases dispoed during last Qtr.		status as on 31.12.2019	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
135226	217.13	482	11.83	786	19.77	134922	209.19

(रिपोर्ट- annexure-19)

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 31.12.2019	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1612	720.41	799	407.05	186	65.24	2225	1062.22

(रिपोर्ट- annexure-20)

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

[राशि करोड़ में]

Notices Issued U/S 13 (2) of SARFAESI Act		Out of which symbolic possession taken under 13(4)		Request sent to Dist Authority for assistance in Physical Possession	Physical Possession taken	No. of cases pending at dist. level
सं	राशि	सं	राशि	सं	सं	राशि
4319	2523.78	1938	958.73	789	129	660

(रिपोर्ट- annexure-21)

ज्ञातव्य हो कि ऋणियों के नाम के साथ बैंको से प्राप्त जिलावार आंकड़ों के अनुसार केवल 270 cases physical possession हेतु जिलों के अधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं। बैंको से बार बार आग्रह के बावजूद इस रिपोर्ट एवं पोर्टल के रिपोर्ट में काफी भिन्नता है जिसपर सभी बैंको द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि पूर्व में SLBC की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार SLBC द्वारा इन 270 cases की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गयी है।

NB: SLBC द्वारा विभिन्न बैंको से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर PMEGP, KCC तथा PMMY योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋण में NPA की स्थिति के आकलन का प्रयास किया गया है। यद्यपि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ों में विसंगतिया है, परन्तु इन आंकड़ों के अध्ययन से NPA की बढ़ती समस्या का पता चलता है।

Scheme	No. of A/Cs	Amt of NPA (Rs in Cr)	% wrt advances in this sector
PMEGP	7643	132.34	40.73%
KCC	404478	1507.94	20.92%
PMMY	58528	93120.09	18.81%

{रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-67 एवं 68 }

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं	70

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMPGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। SLBC द्वारा PMPGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.12.2019 तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved
8150	205.45	1055	24.73	5668	141.25	1340	3364.18

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.12.2019 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है) PMPGP का 2019-20 वित्तीय वर्ष का बैंकवार एवं ज़िलावार लक्ष्य पृष्ठ 72 एवं 73 पर संलग्न है।

8.2 NULM & PMAY

शहरी विकास विभाग से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-70 में दर्शायी गई है।

SEP-I and SHG (NULM) report as on 31.12.2019

No. of applications forwarded to Bank	No. of applications sanctioned	No of applications disbursed	No of applications pending
1526	877	870	649

शहरी विकास विभाग से प्राप्त PMAY से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-71 में दर्शायी गई है।

PMAY Report (31.12.2019) (Amt. in Lakhs)

Source	Application submitted/received during the FY	No. of application sanctioned	Amt Sanctioned	No. of application rejected	No. of applications pending
Govt	2533	1775	37579.06	159	622
Banks	5130	5074	97875.40	28	99

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	13.02.2020
बैठक संख्या	70

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of **31.12.2019**)
झारखंड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंकों के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा है |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित)		1 जिला

AFY 2019-20 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -582 ; प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17460
उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -399 प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 11466
{ विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-75}

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन - 11
भवन निर्माण कार्य लगभग सम्पूर्ण - 02
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 11
भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी - 01

- गिरिडीह एवं जामतारा में भवन निर्माण का कार्य लगभग समाप्ति पर है |
- रामगढ़ RSETI को BOI को हस्तांतरण के संबंध में MoRD द्वारा कार्यवाही की जा रही है अद्यतन जानकारी के अनुसार NACER द्वारा PNB को इस संबंध में सूचित किया गया है,विस्तृत जानकारी अप्राप्त है। भवन निर्माण कार्य से सम्बंधित अंतिम निर्णय होना बाकी है |

(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-76 से 78 में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2018-19 के दौरान		AFY 2019-20 के दौरान	
कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked
17970	1525	11466	2446

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-79 एवं 80 पर उपलब्ध है)

दिनांक 28. 01. 2020 को RSETI Sub-Committee मे प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रशिक्षनार्थी की संख्या 13578 हो चुकी है जो कि लक्ष्य का 78% है। वही क्रेडिट linkage मे भी पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना मे इस वर्ष दिसम्बर तिमाही मे बढ़ोतरी दर्ज की गयी है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर)	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	15
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू	7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है,

झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक - 24 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है।

सितंबर-दिसम्बर 2019 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	1134
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	3391
कुल	4525

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-82 एवं 83 पर उपलब्ध है }

सभी वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) जो झारखंड राज्य में परिचालन कर रहे हैं उनकी विस्तृत जानकारी पृष्ठ संख्या-84 एवं 85 पर उपलब्ध है।

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	13.02.2020
बैठक संख्या	70

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1) प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2) प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2) नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	18.11.2019 अगली बैठक 10.02.2020 को प्रस्तावित

2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 4) स्थानीय निर्यात संस्था 5) उद्योग विभाग 6) एक्जिम बैंक 7) अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी 	<ol style="list-style-type: none"> 1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2) हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन 	13.11.2019 अगली बैठक 07.02.2020 को प्रस्तावित
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक- एसबीआई	<ol style="list-style-type: none"> 1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं /करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती 	29.01.2020
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 	<ol style="list-style-type: none"> 1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष 	13.11.2019 अगली बैठक 07.02.2020 को प्रस्तावित

			7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9) यूनियन बैंक	रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार / बैंकों के पास लंबित मुद्दें 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक / सरकार)	13.11.2019 अगली बैठक 07.02.2020 को प्रस्तावित
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक - एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	02.02.2015 राज्य सरकार को विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति की बैठक आयोजित करने हेतु SLBC से पत्र द्वारा 18.01.2020 को सूचित किया जा चुका है। अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।
7.	एमएसएमई और सरकार प्रायोजित योजनाओं पर उप-	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक - बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और	13.11.2019 अगली बैठक 07.02.2020 को प्रस्तावित

	समिति		6) इलाहाबाद बैंक	वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक-एसबीआई	<ol style="list-style-type: none"> 1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष 	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दे (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	13.11.2019 अगली बैठक के संबंध में उप-समिति के संयोजक SBI द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग को पत्र के द्वारा बैठक आयोजित करने के संबंध में सूचित किया गया है। अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड 	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	अगली बैठक 05.02.2020 को प्रस्तावित
10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	28.01.2020

			6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI		
11	NPA पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, संस्थागत वित्त 2) एसएलबीसी 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 9) केनरा बैंक 10) UCO Bank	राज्य में NPA एवं recovery की स्थिति; DRT, Certificate एवं SARFAESI cases	13.11.2020 अगली बैठक 07.02.2020 को प्रस्तावित
12	Sub Committee on Opening of Banking Outlets	संयोजक एसएलबीसी	संयोजक -एसएलबीसी सदस्य-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि , भारतीय स्टेट बैंक , बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक ।	Uncovered Areas को Cover करने के लिए DFS तथा RBI द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे है। इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए	13.11.2019 अगली बैठक 07.02.2020 को प्रस्तावित

कार्यसूची सं.	11
बैठक की तिथि	13.02.2020
बैठक सं.	70

विविध कार्यसूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 17-10/2018-CSIS दिनांक 10.01.2019 के आदेश के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार SLBC द्वारा सभी बैंको से विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की जानकारी मांगी गयी थी | अद्यतन जानकारी रिपोर्ट 93 एवं 94 के अनुसार राज्य में 2219 आवेदन लंबित है। इससे विदित होता है कि इस दिशा में बैंको द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया जा रहा है | **(Action: सभी बैंक)**

2. **KCC SATURATION DRIVE** – कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 फरवरी 2019 पूरा देश के सभी राज्यों में केसीसी सैचुरेशन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा झारखंड में कुल कृषको की संख्या 39.00 लाख बतायी है तथा केसीसी से वंचित कृषकों की संख्या 3.17 लाख है। प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 91.89 % किसानों को विभिन्न बैंको के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया है। शेष 8.11 % बचे हुए किसानों को KCC से आच्छादित करने की आवश्यकता है। सभी LDMs तथा बैंको को एकीकृत रूप से इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। ज़िलावार विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 34 (a) में संलग्न है। **(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)**

3. **APY CITIZEN'S CHOICE 2020 CAMPAIGN-** PFRDA द्वार 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक पूरे देश भर में APY CITIZEN'S CHOICE 2020 CAMPAIGN की शुरुआत की गई है। इस अभियान में SLBC तथा LDMs को APY enrollment का टारगेट दिया गया है। सभी एलडीएम को इस अभियान के तहत 12 AAPB (Average APY Per Branch) का टारगेट दिया गया है। SLBC को अभियान के अंतर्गत 30,000 APY का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में 02 सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले LDM को PFRDA द्वारा सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ वो सभी LDM जो 12 AAPB के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे उन्हें भी PFRDA द्वारा **Certificates of Excellence** प्रदान किया जाएगा। **(Action: सभी बैंक एवं LDM)**

4. **जन धन दर्शक पोर्टल** -वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के 22 जुलाई 2019 के पत्र के अनुसार झारखंड राज्य के 794 गांव को जन धन दर्शक पोर्टल पर UNCOVERED पाया गया है। इस संबंध में 26 जुलाई 2019 को वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूषण कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी एसएलबीसी व बैंकों के प्रधान कार्यालय से बैठक की। बैठक के आधार पर 30 जुलाई 2019 तक सभी गांव का बैंकिंग आउटलेट से कवरेज रिपोर्ट PMJDY FI-PLAN पोर्टल पर एसएलबीसी को अपलोड करना था। अद्यतन जानकारी के अनुसार राज्य के 811 गांव में से 473 गांव 5 किलोमीटर के रेडियस में बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर किया जा चुका है। शेष 338 गांव को जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा गाँवों को बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर करने के लिए बैंकों में आवंटन कर दिया गया है। DFS ने इसके अतिरिक्त 41 और गाँवों की सूची एसएलबीसी को प्रेषित की

है। ये 41 गाँव भी जन धन दर्शक जीआईएस वेब पोर्टल पर UNCOVERED पाए गए हैं। सभी बैंकों को डीएफएस ने निर्देशित किया है कि 31 मार्च 2020 तक आवंटित गांव को बैंकिंग आउटलेट से कवर कर लिया जाए। इस संबंध में सभी संबंधित बैंकों को गाँवों को कवर करने वाले बैंकिंग आउटलेट्स एवं गांव का विवरण तथा Longitude लाटीट्यूड जन धन दर्शक जी आईएस वेब पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस विषय पर अद्यतन रिपोर्ट में संलग्न है (पृष्ठ 92a से 92)।

(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)

5. Agri Clinics/Agri Business- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित इस केंद्रीय सेक्टर योजना से संबंधित दिशा-निर्देश केंद्रीय विद्यालय मुंबई के परिपत्र संख्या 145/ आईसीडी-35/2011 दिनांक 2 अगस्त 2011 के माध्यम से निर्गत किए गए हैं उल्लेखनीय है कि इस योजना अंतर्गत कृषि संकाय के स्नातकों डिप्लोमा होल्डर्स इत्यादि को कृषि क्लिनिक व कृषि व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज के माध्यम से 2 माह का पूर्णता निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात बैंक ऋण के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है पूर्ण विराम योजना अंतर्गत बैंक वित्त पोषित लाभार्थियों को भारत सरकार से 36 से 44 वर्ष तक के अनुदान का भी प्रावधान है।

इस योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा जहां एक और स्वरोजगार स्थापना को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऋण की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी अतः बैंकों का अपेक्षित सहयोग आवश्यक है योजना की विस्तृत जानकारी व दिशानिर्देश वेबसाइट www.manage.gov.in पर उपलब्ध है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 04.जून 2019 को ईमेल से इस योजना को एसएलबीसी की बैठक में नियमित रूप से शामिल करने का आग्रह किया गया है इस संबंध में ऋण स्वीकृत करने पर इसका रिपोर्ट एसएलबीसी को सभी बैंक नियमित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)

6. पौजी योजनाएँ /असंगठित निकायों-फर्म/कंपनियाँ की अवैध गतिविधियां – जनता से अवैध जमा की मांग / बैंकिंग संबंधी साईबर धोखाधड़ी , फिशिंग इत्यादि की जानकारी। सभी बैंक एवं LDMs से आग्रह है कि इन विषयों से संबन्धित राज्य अंतर्गत मामले एसएलबीसी से सांझा करें। एसएलबीसी उन घटनाओं का संछिप्त विवरण सभी हितधारकों के जागरूकता के लिए एसएलबीसी त्रैमासिक पुस्तक में प्रकाशित करेगी। हालाँकि किसी भी बैंक /LDM के द्वारा इस विषय के संबंध में एसएलबीसी को कोई जानकारी नहीं दी गयी है। **(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)**

7. डिजिटल ज़िला चिन्हित करना-आरबीआई के गवर्नर की 19 जुलाई 2019 को PSBs के MD /ED के साथ बैठक हुई थी। श्री नन्दन निलकेनी की अध्यक्षता में गठित Committee on Deepening of Digital payments के रिपोर्ट तथा आरबीआई के Payment System Vision Document 2021 के आधार पर गवर्नर, RBI ने सभी राज्य के Lead Bank को राज्य के एक ज़िला को चिन्हित कर उस ज़िला को एक वर्ष के समय सीमा में पूर्ण डिजिटल ज़िला करने का लक्ष्य दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वी सिंहभूम ज़िला को इस योजना के लिए चयन किया है। इस प्रक्रिया में बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सभी बैंक, राज्य सरकार, आरबीआई के राज्य कार्यालय का सहयोग अपेक्षित है। श्री अनिल कुमार , मुख्य प्रबन्धक , बैंक ऑफ इंडिया इस योजना के प्रोजेक्ट ऑफिसर है। एलडीएम, पूर्वी सिंहभूम की देख रेख में इस योजना को पूरा करना है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जिला को निर्देशित किया जा चुका है। इस विषय पर राज्य सरकार को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। इस कार्य को संपादित करने के लिए सभी Stakeholder से बैठक कर Roadmap तैयार किया जा चुका है। प्रगति रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 95 में संलग्न है।

(Action:BOI अन्य सभी बैंक RBI, जिला प्रशासन एवं LDM,पूर्वी सिंहभूम)

8. MSME मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा लागू योजनाओं-सचिव, एमएसएमई ,भारत सरकार के द्वारा मुख्य सचिव, झारखंड को 21 अगस्त 2019 को लेटर के माध्यम से राज्य में भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे तीन योजनाओं का व्यापक प्रसार का अनुरोध किया है। एसएलबीसी द्वारा सभी बैंकों को

1. Credit Linked Capital Subsidy Scheme
2. Credit Guarantee Fund Scheme
3. Interest Subvention Scheme for MSME

सभी बैंक से पुनः अनुरोध है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रसार एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. Implementation of Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees: IBA के दिशानिर्देश (पत्र संख्या: PS & BT/SLBC/AES/8342 दिनांक: 9 दिसम्बर,2019) के आलोक में Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees को राज्य में लागू करने हेतु इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। IBA के द्वारा यह बताया गया है कि वर्तमान में यह सुविधा देश की राजधानी नई दिल्ली में लागू है अन्य सभी राज्यों में भी दिल्ली के तर्ज पर इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार को SLBC के द्वारा पत्र के माध्यम से दिनांक 03.02.2020 को सूचित किया जा चुका है।

(**Action:** राज्य सरकार,सभी बैंक)

10. Deepening of Digital Payments के लिए SUB Committee गठित करना: RBI के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.NO.475/02.01.001/2019-20 दिनांक 27.08.2019 के आलोक में SLBC Convenor बैंक को SLBC SUB COMMITTEE ON DIGITAL PAYMENTS गठित करने को कहा था।इस संबंध में SLBC द्वारा सभी स्टकेहोल्डर्स के साथ बैठक की गयी जिसमें इस विषय पर विस्तृत परिचर्चा की गयी। सबकी सहमति से निम्न स्टकेहोल्डर्स को Sub Committee on Digital Payments में शामिल किया गया है।

क) RBI

ख)SLBC

ग)नाबार्ड

घ) Secreatory,Planning cum Finance,GOJ

च) Secreatory,Department of IT,GOJ

छ) Secreatory,Ministry of Rural Development,GOJ

ज)Department of Telecommunication,GOI

झ)Jharkhand Communication Network Ltd.

ट) JSLPS

ठ) Banks

PSB- SBI,BOI, BOB,CANARA BANK,ALLAHABAD BANK, PNB,UNION BANK,INDIAN BANK

PVT BANKS- AXIS BANK, HDFC

PAYMENT BANK-IPPB

CO-OP BANK- JSCB

ढ) BSNL

(**Action:** उपरोक्त सभी Stakeholders)

11. Crop Duration of major crops grown in state of Jharkhand: राज्य के प्रमुख फसलों का Crop duration निर्धारण के लिए RBI द्वारा SLBC को दिशा निर्देश दिया गया है। इस संबंध में द्वितीय Agriculture Sub- Committee की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार SLBC द्वारा Birs Agriculture University से राज्य के प्रमुख फसलों का Crop duration जिसमें Marketing period सम्मिलित हो यह जानकारी मांगी गयी थी। IBAU, राँची द्वारा ईमेल के माध्यम से SLBC को इस संबंध में जानकारी प्रेषित की गयी है। संबंधित जानकारी राज्य सरकार को भी SLBC द्वारा सूचित किया गया है। आगामी Agriculture Sub- Committee की बैठक 10 फरवरी, 2020 को प्रस्तावित है जिसमें अन्य स्टेकहोल्डर्स से परिचर्चा कर 70 वीं SLBC की बैठक में सभा को प्रस्तुत किया जाएगा।

(Action: RBI, SLBC, Agri Department, GOJ, NABARD, All Banks)

12. Developing a Standardized System for data flow and its management by SLBC/ UTLBC Convenor Banks on SLBC/ UTLBC websites: इस संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर SLBC द्वारा बैंको को सूचित किया जा चुका है। RBI ने दिनांक 16 जनवरी 2020 को पत्र के माध्यम से सभी SLBC CONVENOR बैंको को इस विषय के आलोक में उचित दिशा निर्देश दिया था। दिनांक 23.01.2020 को RBI ने ईमेल के द्वारा Block Codes की अद्यतन सूची प्रदान की। SLBC के द्वारा सभी बैंको को 263 Block की सूची ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। सभी बैंको से दिनांक 29.01.2020 तक इस विषय की प्रगति रिपोर्ट मांगी गयी थी। हालांकि केवल 09 बैंको के द्वारा ही इसकी रेपोर्टिंग की गयी है। 07.02.2019 को प्रस्तावित SLBC सब Committee में Monitoring Committee द्वारा सभी बैंको की इस विषय में समीक्षा की जाएगी।

(Action: सभी बैंक)

13. Gram Panchayat Development Plan: DFS के द्वारा एसएलबीसी को GPDP 2020-21 के Implementation में सहयोग करने के लिए पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। एसएलबीसी द्वारा सभी LDMs को इस विषय के अंतर्गत सभी पंचायतों के लिए Frontline workers का ब्योरा मांगा था। साथ ही साथ Frontline workers के Role and Responcibility की जानकारी भी संबंधित सभी Stakeholders से साझा करने को कहा था। सभी LDMs को 2020-21 में आयोजित होने वाले BLBC /DLCC के Agenda में इस विषय पर भी परिचर्चा करनी है।

(Action: सभी बैंक एवं LDM)

कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं	70

Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वान पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है। इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है। राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 31.12.2019 तक राज्य में कुल 46072 POS machines का installation कराया जा चुका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था। यद्यपि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 4.63 लाख credit card, 2.12 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 34.87 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है।

{प्रगति प्रतिवेदन सलग्न-पृष्ठ सं-99 }

बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं	70

NATIONAL BAMBOO MISSION/ राष्ट्रीय बाँस मिशन

बाँस की खेती के लिए नई राह प्रशस्त करने और अच्छी संभावना वाले राज्यों में इसकी मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन प्रारंभ किया गया था। पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन में कई गतिविधियों का प्रावधान है जिनमें ऋण से जुड़ी सब्सिडी घटक शामिल है। नाबार्ड ने भी बैंकों के लिए ऋण अवसरों को निर्देशित करते हुए भारत में बाँस के विकास की एक समन्वित नीति तैयार की है इसे दिनांक 15 फरवरी 2019 को नाबार्ड के पत्र संख्या राबै 1/प्र.का/1317/सी-टैग/पॉलिसी बी- कीपिंग एंड बैम्बू/ 2018-19 के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी बैंक को एवं एसएलबीसी को भेजा गया था। उस पत्र की कॉपी एसएलबीसी झारखंड द्वारा राज्य स्थापित सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय को 5 अगस्त 2019 को पुनः प्रेषित किया गया है। नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से बाँस क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा के बारे में सभी हितधारकों को अवगत कराने के लिए तिमाही बैठक में इस योजना को कार्यसूची के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया है। बैंकों के सभी नियंत्रक प्रमुख से आग्रह है कि इस दिशा में कार्य किया जा सकता है।

कार्यसूची सं.	14
बैठक का दिनांक	13.02.2020
बैठक सं	70

DOUBLING OF FARMERS INCOME BY 2020

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पांच प्रमुख अर्थात् उत्पादकता पानी और कृषि इनपुट की नीतियों में सुधार के द्वारा आय में वृद्धि एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर बाजार मूल्य प्राप्ति और विशेष नीतिगत उपाय अपनाए जा रहे हैं किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित मानकों से संबंधित मुद्दों पर पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित परिणाम हासिल हो सके:-

- क) **Per drop, more crop** को ध्यान में रखते हुए **Irrigation** सिस्टम पर व्यापक ध्यान की आवश्यकता है।
- ख) सभी खेतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीड्स एवं मृदा के हैल्थ के अनुसार **nutrients** की उपलब्धता।
- ग) **Post** हार्वेस्ट **loss** को कम करने हेतु **Warehousing** एवं **Cold Chain** के क्षेत्र में **investment** को बढ़ावा।
- घ) **National farm Market** को विकसित करना तथा कृषि के लिए **e-platform** विकसित करना।
- च) **Food Processing** के द्वारा इस क्षेत्र में **value addition** प्रदान करना।
- छ) **Crop Insurance scheme** को **Strengthening** करना ताकि **Risk** को कम किया जा सके।
- ज) **Ancillaries activity** जैसे पौल्ट्री, **Bee**-कीपिंग एवं **Fisheries** को बढ़ावा।

सरकार आय केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करके कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य बना रही है। किसान के लिए शुद्ध सकारात्मक रिटर्न का एहसास करने के लिए, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से प्रमुख रूप से योजनाओं का प्रचार और कार्यान्वयन किया जा रहा है: - मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना; नीम लेपित यूरिया (NCU); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY); परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY); राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम); प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); बागवानी के विकास के लिए मिशन (MIDH); तिलहन और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP); स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए); कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)। इसके अलावा, वृक्षारोपण (हर मेध पार पेड), मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाएं भी लागू की जाती हैं। ये सभी योजनाएँ कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

फार्मर्स के इंकम को डबल करने के लिए Capital formation की आवश्यकता है इस संबंध में सभी बैंको को Crop loan से संबंधित documentation process को Simplify करने की ज़रूरत है साथ ही साथ त्वरित Sanction एवं disbursement को Specified time लिमिट में करने हेतु भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

LBS के तहत इस agenda को सभी forums जैसे SLBC, DCC, DLRC एवं BLBC की बैठक को रेगुलर अजेंडा में शामिल करना है।

सभी LDMs इस विषय पर Monitoring एवं Progress review के लिए NABARD द्वारा सुझाए Benchmark को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को हर DCC, DLRC की बैठक में शामिल करना चाहिए। (नाबार्ड Circular No: 328/CPD-10/2019 दिनांक 31 December 2019)

इस विषय के संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा leftout/uncovered किसानों की विवरणी SLBC को e-mail द्वारा प्रेषित किया गया है। संबंधित विषय की ज़िलावार विवरणी पृष्ठ संख्या 34 (a) में उपलब्ध है।

कार्यसूची सं.	15
बैठक की तिथि	13.02.2020
बैठक सं	70

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...